E-ISSN: 3048-6041 | Volume-1, Issue-12 | December 2024

गरीबी उन्मूलन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव

प्रियंका रानी [1], प्रो०अंजली प्रसाद [2]
[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी
[2] निर्देशिका, T.P.S. College

Abstract

माइक्रोफाइनेंस गरीबी उन्मूलन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से उन महिलाओं के जीवन में जो सामाजिक और आर्थिक संकटों से जूझ रही हैं। यह महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए साधन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। माइक्रोफाइनेंस द्वारा उन्हें छोटे ऋण प्राप्त करने की संभावना होती है, जो उन्हें व्यावसायिक क्षमता विकसित करने और अपने कार्य को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा, ये कार्य आधारित संगठन भी महिलाओं को उचित जानकारी, शिक्षा, और वित्तीय सलाह प्रदान करने में मदद करते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से, माइक्रोफाइनेंस न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने और सम्मान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है।

स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups,SHG)भी भारत में माइक्रोफाइनेंस का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह। सामूहिक रूप से संगठित होते हैं, जहां स्थानीय महिलाएं एकत्रित होकर साझा बचत और ऋण प्रदान करती हैं। यह समूह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हैं, जहां वित्तीय सेवाओं की कमी होती है।हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2019- 20 स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने तथा देश की विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एसजी को दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी कार्यक्रमों का सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जन धन बैंक खाते वाले स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला असर की सदस्य को ₹5000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी।यह पेपर मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन के माध्यमों से महिलाओं को सशक्त कैसे बनती है, इसका प्रभाव और चुनौतियों को समझेंगे और समस्याओं का पता लगाने का प्रयास करता है।

कीवर्ड :-सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त, बचत ,वित्तीय समावेशन

परिचय:-

गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण, दोनों ही आज के सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महिलाएं पारंपरिक रूप से समाज में कमजोर स्थिति में रही हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, माइक्रोफाइनेंस (Microfinance) ने गरीब महिलाओं को आर्थिक

स्वतंत्रता देने और समाज में उनकी स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्था(एमएफआई) एनजीओ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में मौजूद हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बड़े ऋणदाता हैं जिन्होंने एमएफआई को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाणिज्यिक बैंकों ने समूह उधारकर्ताओं को सीधे ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह का भी लाभ उठाया है। देश में वित्तीय समावेशन एक प्रमुख नीति उद्देश्य के रूप में उभर रहा है। माइक्रोफाइनेंस ने आबादी के बैंकिंग रहित वर्गों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक आशाजनक तंत्र के रूप में केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है। माइक्रोफाइनेंस कम आय वाले ग्राहकों या एकजुट ऋण देने वाले समूहों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें उपभोक्ता और स्व-नियोजित लोग शामिल हैं, जिन्हें सभी वित्तीय सेवाओं से वंचित रखा जाता है। माइक्रोफाइनेंस गरीबों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है और यह एक वित्तीय रूप से व्यवहार्य विकास उपकरण है जिसका उद्देश्य गरीबों को काम करने और गरीबी से बाहर निकलने में सहायता करना है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं जैसी कई तरह की सेवाएँ शामिल हैं।

माइक्रोफाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

• ऋण छोटी राशि के होते हैं- सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म क्रेडिट।

• ऋण बिना किसी संपार्श्विक के प्रदान किए जाते हैं।

• ऋण आमतौर पर ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए लिया जाता है।

• लघु एवं दीर्घ अवधि के ऋण।

• पुनर्भुगतान की उच्च आवृत्ति।

बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस की स्थापना 1983 के दिशा-निर्देशों के तहत की गई थी। माइक्रो फाइनेंस के मूल उद्देश्य जो इसे ऋण वितरण के तरीकों से अलग करते हैं, वे हैं ऋण की छोटी मात्रा, सामाजिक सुरक्षा या सहकर्मी निगरानी पर ध्यान केंद्रित न करना और माइक्रो फाइनेंस से तीन प्रमुख समस्याओं से निपटने की उम्मीद है जो गरीबों के लिए नियोजित किसी भी ऋण वितरण कार्यक्रम की तुलना में है अर्थात् उधारकर्ताओं का लक्ष्य और ऋण अनुबंध का कार्यान्वयन। ग्रामीण बैंक द्वारा प्रवर्तित योजना के तहत, महिला उधारकर्ताओं को संगठित समूह (SHG) बनाया जाता है, जो व्यक्तिगत या समूह की आवश्यकताओं के लिए ऋणदाताओं से उधार लेने में सक्षम होंगे। ये समूह आम तौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं जो महिलाओं को मजबूत बनाते हैं। ऋण भुगतान के हर चरण में पूरे समूह की भागीदारी महत्वपूर्ण है और इसकी उचित निगरानी की आवश्यकता है। कई देशों में, माइक्रो फाइनेंस गैर-सरकारी (एनजीओ) की गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है जो बड़े पैमाने पर या आंशिक रूप से उभरे हुए हैं। इसके साथ माइक्रो के साथ भारतीय प्रयोग दो पहलुओं पर आधारित है। शुरुआत में, भारत ने माइक्रो फाइनेंस को दो प्रमुख पहलुओं पर उपलब्ध कराना शुरू किया।

31 मार्च 2015 तक वित्तीय समावेशन विधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के लिए स्वीकृत धनराशि क्रमशः 181.64 करोड़ और 365.49 करोड़ थी।

• 31 मार्च 2013 तक एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत।

• 75.18 लाख से अधिक बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और 44.51 लाख ऋण से जुड़े समूह थे।

भारत में माइक्रोफाइनेंस

भारत में माइक्रोफाइनेंस आंदोलन की शुरुआत 1992 में नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) से मानी जा सकती है। यह कार्यक्रम बहुत सफल साबित हुआ और भारत में माइक्रोफाइनेंस के सबसे लोकप्रिय मॉडल के रूप में भी विकसित हुआ। भारत में माइक्रोफाइनेंस सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं में नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं।सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के तहत 10.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को कवर करने वाले स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा योगदान है।

वित्त संस्थान:-

एम.एफ.आई. में एन.जी.ओ., ट्रस्ट, सामाजिक और आर्थिक उद्यमी शामिल हैं; ये व्यक्तियों या एस.एच.जी. को छोटे आकार के ऋण देते हैं। वे क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, उत्पादों का विपणन आदि जैसी अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

गरीबी पर माइक्रो फाइनेंस का प्रभाव

एमएफआई और स्वयं सहायता समूह एक ऐसा उपकरण है जो गति को बढ़ाता है, वे अभी भी भारत की चौड़ाई में हैं और अलग-अलग लोगों में प्रवेश करने के लिए और संवाददाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, समावेशन और नवाचार वांछनीय हैं। 'होम डिलीवरी' या 'घर के पास डिलीवरी' की आवश्यकता नहीं है, उदारीकरण और उच्च स्व-सहायता समूह के साथ अधिक से अधिक संस्थान को बार द्वारा वित्तपोषित नहीं किए जाने वाले व्यावसायिक गतिविधियों के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

एमएफआई निम्नलिखित मॉडलों के तहत काम करते हैं।

1.एजेंट के रूप में एमएफआई:- एमएफआई एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और उधारकर्ता और अंतिम पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी लेता है।

2.ऋण धारक के रूप में एमएफआई:- एमएफआई अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण रखता है तथा उन्हें बैंक को बेचने से पहले उन्हें प्रतिभूतिकृत करता है।

3. बैंकिंग सुविधाकर्ता:- बैंकिंग सुविधाकर्ता मध्यस्थ होते हैं जो गांवों या उन क्षेत्रों में बैंकिंग कार्य करते हैं जहां शाखा खोलना संभव नहीं है। जनवरी 2006 में, RBI ने बैंकों को गरीबों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थ के रूप में MFI और NGO की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी।

वित्तीय समावेशन वंचित और निम्न आय वर्ग के विभिन्न वर्गों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन और बेहतर आय के लिए औपचारिक वित्तीय चैनलों की सुविधा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। समय पर पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के वित्तीय तरीकों को शामिल करने के लिए विभिन्न साधनों का आविष्कार और प्रदान करना। वित्तीय समावेशन अपने आप में कभी न खत्म होने वाला, बल्कि एक प्रवेश द्वार, एक प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन उन लोगों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है जो सभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा बचत, ऋण और बीमा सेवाओं जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया:-

जीवन स्तर में सुधार के चक्र में कृषि के बढ़ते व्यावसायीकरण से वित्तीय समावेशन वित्तीय बैंकों को ऋण वितरण का विस्तार करने में मजबूती मिलेगी। यह आर्थिक विकास है। एक और बड़ा आर्थिक योगदान घरेलू वृद्धि हो सकती है, जिसमें कि महिलाओं के जनसंपर्क निर्णय लेने के परिणामों में नकदी,घंटे, स्वयं सहायता समूहों की शिक्षा ने एक आम उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने की सुविधा प्रदान करती है।

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन और बेहतर आय के लिए औपचारिक वित्तीयों की सुविधा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है, समय पर पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के वित्तीय तरीकों को शामिल करने के लिए विभिन्न साधनों का आविष्कार और प्रदान करना। वित्तीय समावेशन अपने आप में कभी न खत्म होने वाला, बल्कि एक प्रवेश द्वार, एक प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन उन लोगों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है जो सभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा बचत, ऋण और बीमा सेवाओं जैसी सुविधाएँ प्रदान करता हैं।

प्राप्त करना और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के वित्तीय तरीकों को शामिल करने के लिए विभिन्न साधन प्रदान करना। वित्तीय समावेशन अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि एक प्रवेश द्वार है, एक प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन उन लोगों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है जो सभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा बचत, ऋण और बीमा सेवाओं जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रियाएं निम्नलिखित है

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में मोटे तौर पर तीन चरण शामिल हैं।

• प्रथम चरण (1960-1990), इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना था।

• दूसरे चरण (1990-2005) में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के एक भाग के रूप में वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की शुरुआत की गई।

• तीसरे चरण (2005) में गैर-बैंक योग्य को बैंक योग्य में बदलने के लिए गरीबी वित्तीय फाइनेंस शुरू किए गए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में समावेशी विकास को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि भारत में समावेशी विकास प्राप्त करना एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण भारत में रहने वाले 600 मिलियन लोगों को मुख्यधारा में लाना बहुत मुश्किल है। समावेशी विकास को प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक वित्तीय समावेशन है। गरीबी का स्तर घट रहा है और विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच के माध्यम से इसमें और कमी आने की संभावना है। परिवारों की आय का स्तर अधिक होगा और साथ ही बचत, उद्यमियों और वित्तीय लेन-देन की संख्या में भी वृद्धि होगी। बैंकिंग के दायरे में आने के लिए इस वर्ग को औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक आसान पहुँच की आवश्यकता होगी। बैंकों को ऐसे ग्राहकों को अपने दायरे में लाने के लिए नए-नए तरीके अपनाने और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नए संभावित ग्राहक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ग्राहक बन जाएँगे। माँग और आपूर्ति पक्ष को पहल करनी चाहिए।

एमएफआई और स्वयं सहायता समूह भारत में गरीबी को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि वे सामूहिक गतिशीलता हैं, फिर भी उन्हें भारत के कोने-कोने में फैलने और भारत के विभिन्न भागों में बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। व्यवसाय सुविधाकर्ताओं और संवाददाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन वित्तीय समावेशन और नवाचारों के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए वांछनीय हैं। बैंकिंग प्रणाली में नए प्रवेशकों को शायद शाखाओं में कदम रखने के बजाय 'होम डिलीवरी' या 'घर के पास डिलीवरी' की आवश्यकता है। बढ़ते उदारीकरण और उच्च आर्थिक विकास के साथ, एमएफआई और स्वयं सहायता समूह की भूमिका भारत में अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को व्यापक ग्राहक आधार से संसाधनों को व्यवस्थित करने और अब तक बैंकों द्वारा वित्तपोषित नहीं की गई व्यावसायिक गतिविधियों को ऋण देने की आवश्यकता है।

माइक्रोफाइनेंस की चुनौतियाँ और सीमाएं

माइक्रोफाइनेंस ने कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन इसके कुछ सीमाएँ और चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं।

उधारी का बढ़ता दबाव: कुछ मामलों में, महिलाओं पर माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से लिया गया ऋण चुकाने का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, खासकर जब व्यापार सफल नहीं हो पाता। इससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है और कभी-कभी वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती हैं।

ऋण की अधिकता: बहुत सी महिलाएं माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग अपने व्यवसायों को बढ़ाने के बजाय निजी खपत के लिए करती हैं। इससे व्यवसाय का विस्तार नहीं हो पाता और उधारी चुकाने में कठिनाई होती है।

प्रशासनिक मुद्दे: माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में अक्सर प्रशासनिक समस्याएँ होती हैं, जैसे कि ब्याज दरों का अत्यधिक होना, ऋण देने में पारदर्शिता की कमी, और असमान वितरण। ये मुद्दे विशेष रूप से गरीब महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

माइक्रोफाइनेंस ने महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे ऋणों के माध्यम से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं और व्यापार शुरू कर सकती हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ समाज में भी सम्मानित होती हैं। हालांकि, महिलाओं को कई सामाजिक और मानसिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पारंपरिक समाज की सीमाएं और परिवार से संबंधित दबाव। इन समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहायक नेटवर्क, आर्थिक और कानूनी जागरूकता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को दीर्घकालिक और स्थिर वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि वे आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज में समान अधिकार प्राप्त कर सकें। इस तरह से, माइक्रोफाइनेंस महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रभावी उपकरण बन सकता है।

संदर्भ सूची:-

●सिंह, ए. (2019) – "Role of Microfinance in Empowering Women Entrepreneurs"
●पाण्डेय, आर. (2017) – "Microfinance and Women Empowerment in India
● कुरुक्षेत्र फरवरी,(2024)
●कुरुक्षेत्र जनवरी, (2024)
●इंटरनेट के द्वारा मदद ली गई है।
●सहायक, आर. (2015) – "Microfinance in Bihar: Trends and Challenges"
●बिहार सरकार की रिपोर्ट (2013-20) "Microfinance and Financial Inclusion in Bihar"
●एनजीओ अध्ययन (2021) – "Impact of Microfinance on Livelihoods in Bihar"
●एम० श्रीवास्तव, मोहम्मद यूनुस का योगदान योजना, 2008
●गुप्ता, "स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्राम भारत का विकास" कुरुक्षेत्र जुलाई-2013
●शर्मा प्रज्ञा,महिला विकास और सशक्तिकरण पोइन्टर पब्लिकेशन, 2001
●आरजू एच०एम०, भारतीय महिला और आधुनिकरण कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन,1993
●अनीता रंजन, "महिला सशक्तिकरण ग्रामीण जीवन",2015
●योजना, "महिला उद्यमिता आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया",2018